

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक ²⁸ मई, 2010

विषय:-वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-09/1-1(102)/2010-11, दिनांक-06 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31(टी0एस0पी0)के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत उद्यान विभाग से सम्बन्धित राज्य सैक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित रू0-5033.00हजार के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0-1285.00हजार (रू0 बारह लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) इस धनराशि का व्यय अनुमोदित परिषद की सीमान्तर्गत केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा।
- (2) धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किस्तों के रूप में किया जायेगा।
- (3) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-187/XXVII(1)/2010, दिनांक-30.03.2010 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (4) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों तथा अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लॉ निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- (8) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को योजनावार अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (9) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

- (10) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- (11) यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय, साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
- (12) वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति आयोजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित/व्यय धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों व लाभार्थियों की सूची विकासखण्डवार/जनपदवार समाज कल्याण विभाग सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष के लिए भी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।
- (13) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।
- (14) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-31 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-00-के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।
- (15) यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-276/XXVII (1)/2010, दिनांक-25 मई, 2010 के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 397 /XVI(1)/10/7(4)/10 तददिनांक,

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त अनुभाग-4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
- 7- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

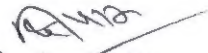
शासनादेश संख्या- 397/XVI(1)/10/7(4)/10, दिनांक- 28 मई, 2010 का संलग्नक
(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र० सं०	लेखाशीर्षक / योजना का नाम/मद	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2010-11	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान सं०-31 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00- आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-00-		
1-	03-उत्तरांचल में जनजाति क्षेत्रों/व्यक्तिगत विकास हेतु औद्योगिक विकास		
	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1000	--
	योग- 03	1000	--
2-	04-राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण		
	02- मजदूरी	700	350
	08-कार्यालय व्यय	15	7
	09-विद्युत देय	10	5
	10-जलकर/जलप्रभार	10	5
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	18	9
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	5
	13-टेलीफोन पर व्यय	80	40
	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/ मोटर गाड़ियों का कय	1	--
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	160	80
	18-प्रकाशन	5	2
	24-वृहद निर्माण कार्य	260	--
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5	2
	29-अनुरक्षण	10	5
	31-सामग्री और सम्पूर्ति	400	200
	42-अन्य व्यय	100	50
	योग-04	1784	760

†

3-	06-मधुमक्खी पालन की योजना		
	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	200	--
	21-छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	50	25
	योग-06	250	25
4-	21-सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास		
	31-सामग्री और सम्पूर्ति	1000	500
	योग-21	1000	500
5-	29-घेरबाड़ योजना		
	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1000	--
	योग-29	1000	--
	कुल योग (राज्य सैक्टर)	6034	1285

(रूपये बारह लाख पिचासी हजार मात्र)


(के०पी०पाटनी)
अनु सचिव।